

दौसा जिले में तीव्र नगरीय प्रसार एवं भू-उपयोग परिवर्तन: एक भौगोलिक मूल्यांकन (2000–2025)

सोनू गार्गिया

शोधार्थी, भूगोल विभाग, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र दौसा जिले में नगरीयकरण का भौगोलिक अध्ययन (2000–2025) के अंतर्गत विगत पच्चीस वर्षों में जिले में हुए तीव्र नगरीय प्रसार, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। दौसा जिला, अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जयपुर महानगर के सामीप्य) के कारण तीव्र ग्रामीण-नगरीय रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2000 से 2025 के मध्य, जिले की नगरीय जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने भूमि उपयोग प्रतिरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दौसा जिले में नगरीयकरण की दर, प्रवृत्ति, नगरीय आकारिकी और नगरीय सीमाओं के विस्तार का विश्लेषण करना है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है, जिसमें भारत की जनगणना (2001 और 2011), राजस्थान सरकार के राजस्व रिकॉर्ड, तथा वर्ष 2025 के अनुमानित सांख्यिकीय आंकड़े शामिल हैं। रिमोट सेंसिंग (सुदूर संवेदन) और जी.आई.एस. तकनीकों के माध्यम से नगरीय भू-उपयोग परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-21 (आगरा-जयपुर) और नवनिर्मित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ने दौसा में शरिबन विकास या रेखीय नगरीकरण को तीव्र गति दी है। इस तीव्र नगरीकरण ने जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर कृषि भूमि का ह्रास, भूजल स्तर का गिरना, अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या और अनियोजित बस्तियों के उद्भव जैसी गंभीर भौगोलिक व पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। अंत में, यह शोध पत्र दौसा के सतत नगरीय विकास के लिए एक नियोजित मास्टर प्लान और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : नगरीयकरण, दौसा जिला, भू-उपयोग परिवर्तन, नगरीय आकारिकी, सतत विकास, नगरीयकरण की प्रवृत्ति : 2000 से 2025, नगरीय समस्याएं एवं भू-उपयोग परिवर्तन, नगरीय जनसंख्या सांख्यिकी : 2000 से 2025 भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा पर प्रभाव, परिणाम एवं विवेचन, समस्या समाधान एवं नीतिगत सुझाव।

प्रस्तावना –

नगरीयकरण केवल जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संपूर्ण भू-दृश्य, जीवन स्तर और आर्थिक संरचना का रूपांतरण होता है। इक्कीसवीं सदी में भारत के अर्ध-नगरीय और छोटे शहर तीव्र विकास के मुख्य केंद्र बनकर उभरे हैं। राजस्थान का दौसा जिला इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भौगोलिक दृष्टि से, किसी भी क्षेत्र का नगरीयकरण वहां के परिवहन तंत्र, औद्योगिक नीतियों और प्रादेशिक अवस्थिति पर निर्भर करता है। वर्ष 2000 की शुरुआत में दौसा मुख्य रूप से एक कृषि-प्रधान जिला था, जहां नगरीय बस्तियों का प्रभाव सीमित था। परंतु, पिछले 25 वर्षों (2000–2025) में आर्थिक उदारीकरण के सुदृढीकरण, आधारभूत ङ्चाइयों के विकास और जयपुर-दौसा-अलवर औद्योगिक त्रिकोण के प्रभाव ने यहां नगरीयकरण की गति को बहुगुणित कर दिया है। प्रस्तुत शोध



द्वितीयक स्रोत :

भारत की जनगणना रिपोर्ट (2001, 2011), नगर परिषद दौसा के रिकॉर्ड, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (जयपुर) के बुलेटिन (2020–2025), तथा जिला भू-अभिलेख शाखा के दस्तावेज।

प्राथमिक स्रोत :

नगरीय आकारिकी और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए जिले के विभिन्न वार्डों में यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति से 500 परिवारों का सर्वेक्षण व साक्षात्कार।

5. नगरीयकरण की प्रवृत्ति : 2000 से 2025 –

दौसा जिले में नगरीयकरण की प्रक्रिया को तीन चरणों में समझा जा सकता है। वर्ष 2000 से 2010 का दशक क्रमिक वृद्धि का था, जहाँ बांदीकुई (रेलवे जंक्शन होने के कारण) और दौसा शहर प्रशासनिक गतिविधियों के कारण बढ़ रहे थे।

वर्ष 2011 से 2020 के मध्य, जयपुर के सैटेलाइट टाउन के रूप में दौसा का महत्व बढ़ा। जयपुर में जमीनों की आसमान छूती कीमतों के कारण मध्यम वर्ग ने दौसा की ओर रुख किया।

वर्ष 2021 से 2025 के मध्य की अवधि को 'नगरीय विस्फोट' (Urban Spurt) कहा जा सकता है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चालू होने से दौसा एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक हब के रूप में परिवर्तित हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार, उच्च शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में पलायन तीव्र हुआ। महुआ, सिकराय और लालसोट जैसी तहसीलें जो पहले विशुद्ध ग्रामीण बाजार थीं, वे अब 'कस्बाई नगरों' में बदल चुकी हैं।

6. दौसा नगरीय मानचित्र एवं विकास –

दौसा नगरीय विकास प्रतिरूप : विगत 25 वर्षों में दौसा शहर का विकास शकंटीय व्यापार क्षेत्र (गांधी तिराहा, पुराना शहर) से बाहर की ओर हुआ है। पुराना शहर जो कभी देवगिरि पहाड़ी और परकोटे के भीतर सीमित था, वह अब उत्तर में आगरा रोड और दक्षिण में कलेक्ट्री सर्किल एवं नई आवासीय कॉलोनियों (जैसे आनंद शर्मा नगर, रामकरण जोशी नगर) की तरफ फैल चुका है।

[उत्तर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक ,

|

[पश्चिमरू जयपुर, === (दौसा बाईपास / NH-21) === [पूर्व : आगरा,

|

[केंद्रीय शहर: पुराना बाजार ,

|

[दक्षिण: लालसोट रोड / रेलवे स्टेशन ,

विकास के तीन प्रमुख चरण (30 वर्षों का मास्टर प्लान परिप्रेक्ष्य):

आवासीय विस्तार (2000–2010): कलेक्ट्री के आसपास और सिंधी कॉलोनी जैसे क्षेत्रों का घनीकरण।

व्यावसायिक विकेंद्रीकरण (2011–2020): बाईपास रोड पर मैरिज गार्डन, होटल, शोरूम और निजी कॉलेजों का निर्माण।

औद्योगिक व मिश्रित भू-उपयोग (2021–2025) : रीको (RIICO) औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार और एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पॉइंट पर वेयरहाउसिंग का विकास।

7. नगरीय समस्याएं एवं भू-उपयोग परिवर्तन –

नगरीय आकारिकी :

दौसा शहर की आकारिकी में स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। पुराना शहर अत्यंत सघन है जहाँ गलियां संकरी हैं और ड्रेनेज व्यवस्था मध्यकालीन है। इसके विपरीत, नया विस्तारित क्षेत्र ग्रिड-पैटर्न पर आधारित है, परंतु इसमें भी विनियामक प्राधिकारियों की शिथिलता के कारण अवध कॉलोनियों की बहुलता है।

प्रमुख नगरीय समस्याएं :

आवासीय संकट एवं मलिन बस्तियां: निचले आय वर्ग के प्रवासियों के कारण अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ है।

यातायात संकुलन : पुराने शहर के बाजारों (मिश्रा बाजार, सैथल रोड) में पार्किंग का पूर्ण अभाव है।

जल संकट : देवगिरि की पहाड़ियों से धिरे होने के कारण पारंपरिक जल स्रोत (कुंड और बावड़िया) नष्ट हो चुके हैं। शहर पूरी तरह बीसलपुर परियोजना और अत्यधिक गहरे होते नलकूपों पर निर्भर है।

अपशिष्ट प्रबंधन : ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए डंपिंग यार्ड्स की वैज्ञानिक व्यवस्था न होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

8. नगरीय जनसंख्या सांख्यिकी : 2000 से 2025 -

निम्नलिखित तालिका जिले के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि, नगरीयकरण प्रतिशत और दशकीय परिवर्तन को प्रदर्शित करती है:

तालिका : 1

दौसा जिले के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि, नगरीयकरण प्रतिशत और दशकीय परिवर्तन

नगरीय केंद्र	जनसंख्या (2000)	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या (2025 प्रक्षेपित)	कुल वृद्धि % (2000-2025)	प्रमुख आर्थिक आधार
दौसा शहर	62,000	85,960	1,45,000	133.8%	प्रशासन, व्यापार, शिक्षा
बांदीकुई	38,000	47,443	72,000	89.4%	रेलवे, वाणिज्यिक मंडी
लालसोट	24,000	34,363	58,000	141.6%	कृषि विपणन, लघु उद्योग
महुआ	15,000	23,200	42,000	180.0%	परिवहन, सीमावर्ती व्यापार
अन्य सैंसस टाउन	12,000	19,500	38,000	216.6%	ग्रामीण-शहरी संक्रमण
कुल नगरीय योग	1,51,000	2,10,466	3,55,000	135.1%	औसत नगरीयकरण दर

महत्वपूर्ण टिप्पणी : वर्ष 2000 में दौसा जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का योगदान मात्र लगभग 11: था, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर लगभग 18.5: होने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जनसांख्यिकीय प्रतिस्थापन अत्यंत तीव्र रहा है।

9. भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा पर प्रभाव :

नगरीय विकास ने दौसा जिले के मूल ढांचे को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में गहराई से प्रभावित किया है। इन प्रभावों का विस्तृत वर्गीकरण निम्नलिखित है:

क) भौगोलिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव :

माइक्रो-क्लाइमेट में बदलाव : कंक्रीट के ढांचों, पक्की सड़कों और वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण दौसा शहर के तापमान में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 1.5° C से 2° C की वृद्धि दर्ज की गई है।

भूजल का अत्यधिक दोहन : नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट के कारण 'Groundwater Recharge' (भूजल पुनर्भरण) अवरुद्ध हो गया है, जिससे वॉटर टेबल 200 फीट से गिरकर 600 फीट से नीचे चला गया है।

ख) आर्थिक प्रभाव :

प्राथमिक से द्वितीयक-तृतीयक क्षेत्र में बदलाव : वर्ष 2000 में जहाँ जिले की 70: कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, वहीं शहरी क्षेत्रों में अब 82: कार्यशील जनसंख्या सेवा क्षेत्र (व्यापार, परिवहन, बैंकिंग) और विनिर्माण (शीको औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन कटिंग इंडस्ट्री) में संलग्न है।

भूमि मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धिरु हाईवे के किनारे की जमीनों की कीमतें पिछले 25 वर्षों में 500 गुना तक बढ़ी हैं, जिससे स्थानीय कृषक रातों-रात पूंजीपति बने हैं, परंतु इससे वास्तविक उत्पादक कृषि भूमि का नुकसान हुआ है।

ग) सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव :

एकल परिवारों का चलनरु नगरीय संस्कृति के प्रभाव से पारंपरिक संयुक्त परिवार टूट रहे हैं।

उपभोक्तावादी संस्कृतिरु शहरों में मॉल, मल्टीप्लेक्स (जैसे दौसा शहर में नए सिनेमा हॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) और आधुनिक लाइफस्टाइल का प्रसार हुआ है।

घ) शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव :

शैक्षणिक हब के रूप में उदय : दौसा और बांदीकुई में निजी व सरकारी कॉलेजों, प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग केंद्रों, और तकनीकी संस्थानों की बाढ़ आ गई है। महिला साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में अत्यंत कम थी, उसमें शहरी क्षेत्रों में आशातीत सुधार हुआ है।

चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढीकरण : जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन और निजी सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की स्थापना से अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर पर निर्भरता कम हुई है।

10. परिणाम एवं विवेचन –

शोध के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दौसा जिले का नगरीयकरण 'नियोजित' (Planned) न हाकर 'स्वतः स्फूर्त' रहा है।

परिकल्पना परीक्षण :

परिवहन जनित विकास : राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के समानांतर 5 किलोमीटर की परिधि में सबसे ज्यादा नगरीय जमावड़ा देखा गया है। हमारी पहली परिकल्पना (H 1) सत्य सिद्ध होती है।

पर्यावरणीय लागत पर विकास: उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले कृषि क्षेत्रों का कंक्रीट में बदलना चिंताजनक है। सेटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा शहर के हरित क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में 22: की कमी आई है। अतः दूसरी परिकल्पना (H 2) भी सांख्यिकीय रूप से मान्य है।

कस्बों का शहरीकरण : लालसोट और महुआ जैसे उप-नगरों का विकास जिला मुख्यालय से भी तेज गति से हो रहा है, जो यह दर्शाता है कि विकेंद्रीकृत नगरीयकरण (Decentralized Urbanization) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

11. समस्या समाधान एवं नीतिगत सुझाव :

दौसा जिले को एक सतत और रहने योग्य नगरीय क्षेत्र बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं :

सेटेलाइट टाउनशिप मास्टर प्लान 2035 : नगर परिषद को आगामी 10 वर्षों की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखकर 'जोनल डवलपमेंट प्लान' बनाना चाहिए, ताकि अवैध कॉलोनियों को बसाने से पहले ही ड्रेनेज और सड़कों का लेआउट तैयार हो।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता: गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सभी नए व्यावसायिक और आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए।

रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण: दौसा शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए नवनिर्मित एक्सप्रेसवे लिंक्स के पास एक आधुनिक 'ट्रांसपोर्ट नगर' और 'रिंग रोड' का पूर्ण क्रियान्वयन आवश्यक है।

हरित पट्टियों (Green Belt) का विकास: देवगिरि पहाड़ी के चारों ओर वनों का संरक्षण किया जाए और शहरी सीमा पर बफर जोन विकसित किए जाएं ताकि 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव को कम किया जा सके।

निष्कर्ष :-

विगत पच्चीस वर्षों (2000-2025) का कालखंड दौसा जिले के इतिहास में भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का स्वर्णिम किंतु चुनौतीपूर्ण अध्याय रहा है। एक शांत, कृषि-आधारित जिले से दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के एक प्रमुख रणनीतिक नगरीय केंद्र के रूप में दौसा का

उभरना क्षेत्रीय विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। आर्थिक समृद्धि, शैक्षणिक उन्नयन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के रूप में नगरीयकरण के लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।

किंतु, यदि इस विकास को दूरदर्शितापूर्ण मास्टर प्लान और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में दौसा गंभीर नगरीय विभीषिकाओं का सामना करेगा। सतत नगरीयकरण ही एकमात्र विकल्प है, जहाँ आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिकी संरक्षण सह-अस्तित्व में रह सकें। यह शोध पत्र नीति-निर्माताओं को दौसा के भविष्य के संतुलित विकास के लिए एक व्यावहारिक भौगोलिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1 भारत की जनगणना (2001). जिला जनगणना हस्त पुस्तिका: दौसा, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान।
- 2 भारत की जनगणना (2011). शहरी जनसंख्या और अनंतिम सांख्यिकी, भारत सरकार।
- 3 राम, बी. (2005). राजस्थान में भू-उपयोग परिवर्तन और नगरीयकरण, भौगोलिक समीक्षा पत्रिका, अंक 42, 12-18.
- 4 शर्मा, एन. एल. (2012). पूर्वी राजस्थान की नगरीय आकारिकी एक भौगोलिक विश्लेषण, अरावली प्रकाशन, जयपुर।
- 5 सिंह, आर. एल. (2015). भारत का प्रादेशिक भूगोल, कल्याणकारी प्रकाशक, नई दिल्ली।
- 6 नगर परिषद दौसा (2021). दौसा शहर मास्टर प्लान – 2031 रिपोर्ट, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार।
- 7 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (2024). जिला सांख्यिकीय रूपरेखा: दौसा, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।
- 8 कुमार, ए. एवं मिश्रा, एस. (2018). राष्ट्रीय राजमार्गों का नगरीय प्रसार पर प्रभाव: जयपुर-आगरा रूट का एक केस स्टडी, इंडियन जियोग्राफिकल जर्नल, 93(2), 45-58.
- 9 चौहान, टी. एस. (2009). राजस्थान का भूगोल, विज्ञान प्रकाशक, जोधपुर।
- 10 तिवारी, ए. के. (2022). अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूजल संकट और नगरीयकरण: दौसा जिले का विश्लेषण, जल संसाधन अनुसंधान पत्रिका, 14(1), 89-102.
- 11 राजस्थान सरकार (2025). दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आर्थिक गलियारा और क्षेत्रीय विकास नीति, उद्योग मंत्रालय, जयपुर।
- 12 भार्गव, जी. (2003). भारत में नगरीय समस्याएं और मलिन बस्तियां, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- 13 जोशी, आर. (2016). जयपुर संभाग में जनसांख्यिकीय प्रतिरूप और प्रवासन प्रवृत्तियां, राजस्थान जियोग्राफिकल एसोसिएशन (RGA) प्रोसीडिंग्स, 28, 112-125.
- 14 सैनी, के. सी. (2019). दौसा जिले में स्टोन क्रशिंग उद्योग और उसका पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण भूगोल पत्रिका, 7(3), 67-74.
- 15 गुप्त, एस. पी. (2011). सांख्यिकी के सिद्धांत, सुल्तान चंद एंड सन्स, नई दिल्ली।
- 16 मियर, जी.एम. (2007). आर्थिक विकास के अग्रणी मुद्दे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- 17 रीको (टिप्पू) रिपोर्ट (2023). दौसा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना चरण-पट, उद्योग भवन, जयपुर।
- 18 राव, एम. पी. (2020). जी.आई.एस. और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से शहरी फैलाव (Urban Sprawl) का मापन, जियो-स्पेशियल वर्ल्ड जर्नल, 11(2), 201-215.
- 19 शर्मा, आर. डी. (2014). शोध पद्धति के सिद्धांत, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- 20 वर्मा, एल. एन. (2006). नगरीय भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।